



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 220]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 29, 2014/भाद्रपद 7, 1936

No. 220]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 29, 2014/BHADRA 7, 1936

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

(निर्णायक समीक्षा)

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2014

विषय : चीन जन. गण., कोरिया आर.पी. और चाईनिज ताईपय में उदभिवत अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियोल के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की निर्णायक समीक्षा की शुरूआत

सं.15/18/2014-डीजीएडी :—यतः समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे एतदपश्चात पाटनरोधी नियमवली कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) ने चीन जन.गण., कोरिया आर.पी. और चाईनिज ताईपय (जिन्हें एतदपश्चात् “संबद्ध देश” कहा गया है) में उदभिवत अथवा वहां से निर्यातित फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियोल (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद कहा गया है) के आयातों पर दिनांक 22-07-2009 की अपनी अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/19/2008 के तहत एक निर्णायक समीक्षा में पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित करने की सिफारिश की थी और वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 31-08-2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 89/2009-सीमाशुल्क के तहत इस शुल्क का उद्ग्रहण किया गया था ।

2. यतः, सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम में उल्लिखित शर्तों के अनुसार अधिरोपित पाटनरोधी शुल्क, जब तक उसका पहले प्रतिसंहरण नहीं कर दिया जाता है, ऐसे अधिरोपण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर निष्प्रभावी हो जाती है और उपर्युक्त प्रावधान के होते हुए भी, ऐसे साधन की समाप्ति होने से पहले युक्तियुक्त समायावधि के अंदर घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से विधिवत साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी को यह समीक्षा करना अपेक्षित होता है कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन एवं क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

समीक्षा के लिए अनुरोध

3. और यतः, उपर्युक्त प्रावधान के अनुरूप, मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने प्राधिकारी के समक्ष एक विधिवत साक्ष्यांकित याचिका यह आरोप लगाते हुए दायर की है कि संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के आयातों पर शुल्क प्रभावी होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी हुई है और प्राधिकारी से अनुरोध किया है कि वह संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिनांक 31.08.2009 की सीमाशुल्क अधिसूचना संख्या 89/2009-सीमाशुल्क के तहत उदग्रहित पाटनरोधी शुल्क और उसकी निरन्तरता की द्वितीय निर्णायक समीक्षा प्रारंभ करे। यह अनुरोध इस आधार पर आधारित है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद पाटन की निरंतरता बनी रही और घरेलू उद्योग को संबद्ध देशों से पाटन के कारण क्षति की निरन्तरता बनी रही क्योंकि प्रभावी पाटनरोधी शुल्क की प्रमात्रा एवं उसका स्वरूप अपर्याप्त है। आवेदक ने पुनः यह तर्क दिया है कि संबद्ध देशों के विरुद्ध इस साधन की समाप्ति के परिणामस्वरूप पाटन एवं घरेलू उद्योग को क्षति की निरंतरता बने रहने अथवा उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। आवेदक ने यह भी दावा किया है कि पाटनरोधी शुल्क का प्रतिसंहरण कर लेने के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति और भी अधिक बढ़ जाएगी, इसलिए इस शुल्क को अगले पांच वर्षों तक की अवधि के लिए बढ़ाना अपेक्षित है।

4. और यतः, प्राधिकारी संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन और घरेलू उद्योग को होने वाली कथित क्षति के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर इस बात पर विचार करता है कि लागू प्रतिपाटन शुल्क की सेनसेट समीक्षा की कार्रवाई शुरू करना संबद्ध देशों से आफ सेट पाटन की तरफ इस प्रकार के शुल्क को जारी रखने की आवश्यकता की जांच पड़ताल जारी रखने के लिए समुचित होगा तथा इस प्रकार की जांच पड़ताल करने के लिए समुचित होगा कि क्या कि यदि संबद्ध देशों से शुल्क को हटा लिया जाता है अथवा अलग-अलग दरों में रखा जाता है तो क्या घरेलू उद्योग को इससे क्षति होते रहने अथवा इसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

घरेलू उद्योग एवं आधार

5. यह याचिका मैसर्स मनाली पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (जिसे एतदपश्चात् "याचिकाकर्ता" कहा गया है) द्वारा दायर की गई है। प्राधिकारी के पास उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार याचिकाकर्ता का उत्पादन जांच की अवधि में विचाराधीन उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा अनुपात था इसलिए याचिकाकर्ता नियमों के आशय के अंतर्गत आधार के मापदंड को पूरा करता है तथा घरेलू उद्योग है। याचिकाकर्ता ने यह प्रमाणित किया है कि प्रस्तावित जांच की अवधि के दौरान याचिकाकर्ता या उससे संबद्ध किसी अन्य पक्षकार द्वारा विचाराधीन उत्पाद का नियम 2(ख) के आशय के अंतर्गत आयात नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने यह भी प्रमाणित किया है कि नियम के आशय के अंतर्गत संबद्ध देशों के किसी निर्यातक से भी उसका कोई संबंध नहीं है।

विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

6. मूल जांच में विचाराधीन उत्पाद 3000 से 4000 आण्विक भार का फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियोल था। निर्णायक समीक्षा जांच के लिए वर्तमान याचिका में भी विचाराधीन उत्पाद में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वाणिज्यिक एवं बाजार की बोलचाल में फ्लेक्सिबल स्लैबस्टॉक पालियोल को सामान्यतः एफएसपी के रूप में जाना जाता और उसे इस जांच में एफएसपी रूप में ही उल्लिखित किया गया है। इस संबद्ध वस्तु का प्रयोग स्लैबस्टॉक फोम आदि का विनिर्माण करने के लिए किया जाता है। इस विचाराधीन उत्पाद को सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 39 में "प्लास्टिक एवं उसकी वस्तुएं" श्रेणी के अंतर्गत और इसके अतिरिक्त, सीमाशुल्क वर्गीकरण के अनुरूप 39072010 और 39072090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि यह वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी रूप में वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

7. इसके अतिरिक्त, इस तथ्य के प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध पाटित वस्तु घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के समान हैं। पाटित आयातों तथा घरेलू रूप से उत्पादित संबद्ध वस्तु के तकनीकी विनिर्देशनों, प्रकार्यों एवं अंतिम प्रयोगों में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं तकनीकी एवं वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इसलिए, घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु तथा संबद्ध देशों से पाटित वस्तु नियमों के अनुसार "समान वस्तु" हैं।

अंतर्ग्रस्त देश

8. वर्तमान जांच में अंतर्ग्रस्त देश चीन जन.गण., कोरिया आर.पी. और चाईनिज ताईपय है।

जांच की अवधि

9. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 (12 माह) है। तथापि, क्षति विश्लेषण करने के प्रयोजनार्थ विगत तीन वर्षों अर्थात् अप्रैल, 2010 से मार्च 2011, अप्रैल, 2011 से मार्च 2012, अप्रैल 2012 से मार्च, 2013 तथा जांच की अवधि (पीओआई) के आंकड़ों पर भी विचार किया गया है।

प्रक्रिया

10. इस जांच से यह निर्धारण होगा कि क्या इन उपायों के समाप्त होने से पाटन और क्षति होना जारी रहेगा अथवा उनकी पुनरावृत्ति होती रहेगी। प्राधिकारी इस आशय की जांच पड़ताल करेगा कि क्या ड्यूटी के लगाये रखने को जारी रखना आफसेट पाटन के लिए आवश्यक है और क्या यदि ड्यूटी को हटा दिया जाता है अथवा इसमें परिवर्तन किया जाता है तो क्या इसे क्षति जारी रहेगी अथवा उनकी पुनरावृत्ति होगी।

- i. यह समीक्षा दिनांक 22.07.2009 की अपनी अंतिम जांच-परिणाम अधिसूचना संख्या 15/19/2008 और दिनांक 31.08.2009 की अधिसूचना सं. 89/2009-सीमा शुल्क के सभी पहलुओं को अपने दायरे में शामिल करेगी।
- ii. नियमावली के नियम 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 और 20 के प्रावधान इस समीक्षा में यथाआवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

पाटनरोधी जांच की शुरुआत

11. प्राधिकारी विगत तर्कों को ध्यान में रखते हुए, संबद्ध देशों में उदभवित अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव की जांच करने के लिए पाटनरोधी निर्णायक समीक्षा जांच प्रारंभ करते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

12. सम्बद्ध देशों के निर्यातकों तथा उनकी सरकार को भारत स्थित उनके राजदूतावासों के जरिए और भारत में इस संबद्ध वस्तु से संबंधित ज्ञात आयातकों और उनके प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को निर्धारित स्वरूप और ढंग से सभी संगत जानकारी दर्ज करने और प्राधिकारी को अपने विचारों से निम्नलिखित पते पर अवगत करने के लिए अलग से संबोधित किया जा रहा है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग
नई दिल्ली-110001

13. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे उल्लिखित समय सीमा के अंदर विहित स्वरूप और ढंग से जांच से संगत सूचना प्रस्तुत कर सकता है। प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय प्रस्तुतिकरण करने वाले किसी अन्य पक्षकार को उसका अगोपनीय पाठ अन्य पक्षकारों को उपलब्ध कराने के लिए प्रस्तुत करना भी अपेक्षित होगा।

समय-सीमा

14. वर्तमान जांच से संबंधित किसी सूचना को लिखित रूप में इस तरह से प्रेषित किया जाना चाहिए जिससे कि वह प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से (40 दिनों) चालीस दिनों से अनधिक समय में पहुँच जाए। यदि निर्धारित समय-सीमा के अंदर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्ष दर्ज कर सकते हैं।

15. वर्तमान मामले में सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे अपने हित (हित की प्रकृति सहित) की सूचना दें तथा अपने प्रश्नावली प्रत्युत्तर दायर करें और घरेलू उद्योग के आवेदनपत्र पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चालीस दिनों (40 दिनों) के अंदर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करें। यह सूचना हार्ड कापी और साफ्ट कापी दोनों रूपों में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

16. प्रश्नावली प्रत्युत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष किसी प्रस्तुतिकरण (इससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) करने वाले पक्षकारों से इसे दो पृथक सेटों में, यदि इसके किसी भाग पर "गोपनीयता" का दावा किया जाता है, फाइल किया जाना अपेक्षित है:-

(क) एक सेट गोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो, और

(ख) एक अन्य सेट अगोपनीय के रूप में (शीर्षक, पृष्ठों की संख्या, अनुक्रमणिका, आदि सहित) चिन्हित किया गया हो।

17. "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" की प्रस्तुति को प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर "गोपनीय" अथवा "अगोपनीय" रूप में स्पष्टतः चिन्हित किया जाना चाहिए। ऐसे चिन्हांकन के बिना की गई प्रस्तुति प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय के रूप में समझी जाएगी और प्राधिकारी इस बात के लिए स्वतंत्र होंगे कि ऐसी प्रस्तुति का निरीक्षण करने के लिए वह अन्य इच्छुक पक्षकारों को अनुमति प्रदान करे। दोनों संस्करणों की सॉफ्ट प्रति भी प्रत्येक के पांच (5) सेटों में हार्ड कापी के साथ प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।

18. गोपनीय संस्करण में ऐसी सभी सूचनाएँ समाविष्ट होंगी जो गोपनीय प्रकृति की हो और/अथवा अन्य सूचना जिसके बारे में ऐसी सूचना का प्रदाय करने वाला गोपनीय के रूप में दावा करता हो। सूचना जिसकी प्रकृति में गोपनीयता के रूप में दावा किया जाता है अथवा सूचना जिस पर अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया जाता है, के लिए, सूचना आपूर्तिकर्ता से प्राप्त सूचना कि ऐसी सूचना क्यों प्रकट नहीं की जा सकती है, के साथ एक उचित कारण दिया जाना अपेक्षित है।

19. अगोपनीय संस्करण सूचना अनुक्रमित अथवा रिक्त किए गए (यदि अनुक्रमणिका सम्भव न हो) और जिस पर गोपनीयता का दावा किया गया हो, के आधार पर सार रूप में की गई गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय संस्करण की प्रतिकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सार इतने विस्तृत रूप में हो कि उससे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सार की पर्याप्त समझ प्राप्त हो सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी सूचना का सार प्रस्तुत करना संभव नहीं है और उसके कारणों का स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए कि उसका सार प्रस्तुत करना संभव क्यों नहीं है।

20. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जाँच करने के पश्चात गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए किया गया अनुरोध वांछित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता उस सूचना को सार्वजनिक करने का या तो इच्छुक नहीं है या उसका सामान्यीकृत अथवा सारांश रूप में प्रकटीकरण करने को प्राधिकृत करना नहीं चाहता है तो प्राधिकारी ऐसी सूचना की अवहेलना कर सकते हैं।

21. सार्थक अगोपनीय पाठ के बिना अथवा गोपनीयता की दावे के संबंध में सद्कारण के बिना किए गए किसी भी प्रस्तुतिकरण को प्राधिकारी द्वारा रिकार्ड में नहीं लिया जाएगा।

22. प्रदान कराई गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लिए जाने पर प्राधिकारी ऐसी सूचना प्रदान कराने वाले पक्षकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत किए बिना किसी भी पक्षकार को उस सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

23. प्राटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुरूप कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के अगोपनीय पाठ युक्त सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

असहयोग

24. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार किसी सूचना की पहुंच तक मनाही करता है और युक्तिसंगत अवधि के अंदर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है अथवा जांच में भारी व्यवधान उत्पन्न करता है तो प्राधिकारी उनको उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्रीय सरकार को समुचित सिफारिशें कर सकते हैं।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department Of Commerce)

DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 28th August, 2014

(Sunset Review)

Subject : Initiation of sunset Review anti dumping investigation concerning imports of Flexible Slabstock Polyol originating in or exported from China PR, Korea RP and Chinese Taipei.

15/18/2014-DGAD –Whereas, in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein after referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (herein after referred to as the Rules), the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) vide its Final Findings Notification No 15/19/2008 dated 22.07.2009, had recommended in a sunset review investigation, the imposition of anti-dumping duties on the imports of Flexible Slabstock Polyol (hereinafter referred to as the subject goods or Product Under Consideration or FPS), originating in or exported from China PR, Korea RP and Chinese Taipei (herein after referred to as the subject countries) and the duties were levied by the Ministry of Finance vide Customs Notification No.89/2009-Customs dated 31.08.2009.

2. Whereas, in terms of the Customs Tariff Act, the antidumping duty imposed shall unless revoked earlier cease to have effect on the expiry of five years from the date of such imposition. And, notwithstanding the above provision, the Authority is required to review, on the basis of a duly substantiated request made by or on behalf of the domestic industry within a reasonable period of time prior to the date of the expiry of the measure, as to whether the expiry of duty is likely to lead to continuation or recurrence of dumping and injury.

Request for Review

3. And whereas, in terms of the above provision, Manali Petrochemicals Limited has filed a duly substantiated petition before the Authority alleging continued dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries in spite of duties in force and has requested the Authority for initiation of second sunset review of the anti-dumping duties levied by the Central Government on the subject goods originating in or exported from these countries vide Customs Notification No.89/2009-Customs dated 31.08.2009 and continuation of the same. The request is based on the grounds that dumping has continued in spite of imposition of antidumping duty on the import of the subject goods from the subject countries and the domestic industry continues to suffer injury on account of dumping from the subject countries as the form and quantum of anti dumping duty in force has been insufficient. The applicant has further argued that expiry of the measure against the subject countries would be likely to result in continuation or recurrence of dumping and injury to the domestic industry. The applicant also claims that revocation of anti-dumping measures

would result in intensified injury to the domestic industry and, therefore, the duty is required to be continued for a further period of five years.

4. And, the Authority, on the basis of prime facie evidence of dumping of the subject goods from the subject countries and likely injury to the domestic industry, considers that initiation of sunset review proceedings for the anti-dumping duties in force would be appropriate to examine the need for continuation of such duties to offset dumping from the subject countries and to examine as to whether the injury to the domestic industry is likely to continue or recur if the duties were removed or varied from the subject countries.

Domestic Industry and Standing

5. The petition has been filed by M/s Manali Petrochemicals Ltd (hereinafter referred to as 'petitioner'). As per the records available with the Authority, the petitioner accounts for major proportion of the product under consideration in the total domestic production in the period of investigation and, therefore, constitutes Domestic Industry as well satisfies the criterion of standing within the meaning of the Rules. The petitioner has certified that there are no imports of the product under consideration during proposed POI by the petitioner or any of its related party within the meaning of Rule 2(b). The petitioner has also certified that it is not related to any of the exporters from the subject countries in terms of the Rules.

Product Under Consideration and Like Article

6. The product under consideration in the original investigation was Flexible Slabstock Polyol of molecular weight 3000 to 4000. In the present petition for sunset review investigation, there is no change in the product under consideration. Flexible Slabstock Polyol is generally known as "FSP" in the commercial and market parlance and has been referred to as FSP as well in this investigation. The subject goods are used for manufacture of slabstock foam, etc. The product under consideration is classified under the category "Plastics and articles thereof" in Chapter 39 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under 39072010 and 39072090 as per Customs Classification. However, Customs classification is indicative only and no way binding on the scope of the present investigation.

7. Further, there is prima facie evidence that the subject goods being imported are identical to the goods produced by the domestic industry. There are no differences either in the technical specifications, functions or end-uses of the dumped imports and the domestically produced subject goods. The two are technically and commercially substitutable also. Hence, the goods produced by the domestic industry are 'Like Article' to dumped goods from the subject countries in terms of the Rules.

Countries Involved

8. The countries involved in the present investigation are the China PR, Korea RP and Chinese Taipei.

Period of Investigation

9. The period of investigation (POI) for the purpose of present investigation is 1st April 2013 to 31st March, 2014 (12 months). However, for the purpose of analyzing injury, the data of previous three years, i.e., April 2010 to March 2011, April 2011 to March 2012, April 2012 to March-2013 and the period of investigation (POI) will be considered.

Procedure

10. The investigation will determine as to whether the continued imposition of the duties is necessary to offset dumping and whether the injury would be likely to continue or recur if the duty were removed or varied, or both.

- i. The review will cover all aspects of Final Findings Notification No 15/19/2008 dated 22.07.2009 and Customs Notification No. 89/2009-Customs dated 31.08.2009.
- ii. The provisions of Rules 6,7,8,9,10,11,16,17,18,19 and 20 of the Rules supra shall be mutatis mutandis applicable in this review.

Initiation Of Anti Dumping Investigation

11. The Authority, in view of the foregoing, initiates sunset review anti-dumping investigation into the existence, degree and effect of alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries.

Submission of Information

12. The exporters in the subject countries, their governments through their Embassies in India, the importers and users in India known to be concerned and the domestic industry are being addressed separately to submit relevant information in the form and manner prescribed and to make their views known to the Authority at the following address:

The Designated Authority
Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties
Ministry of Commerce and Industry
Department of Commerce
4th Floor, Jeewan Tara Building, Parliament Street, New Delhi

13. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the prescribed form and manner within the time limit set out below. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

14. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

15. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of publication of this Notification. The information must be submitted in hard copies as well as soft copies.

Submission of information on confidential basis

16. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- (a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- (b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

17. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (5) sets of each.

18. The confidential version shall contain all information which are by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information can not be disclosed.

19. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.

20. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

21. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without a good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

22. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

23. In terms of Rule 6(7) of the AD Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

24. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

J K DADOO, Designated Authority